साक्षरता दर बिहार में है, देश में सर्वाधिक निरक्षरता बिहार में है, school dropout rate सबसे अधिक बिहार में है, तो महोदय, समुचित विकास एवं औद्योगीकरण के अभाव में शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है, ऐसा रास्ता है, जिससे हम बिहार जैसे राज्य को पिछड़ेपन और गरीबी के दुष्चक्र से निकाल कर प्रगति पथ पर ले जा सकते हैं। कम खर्च पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिहार में केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालयों की अधिक-से-अधिक आवश्यकता है।

महोदय, हम जानना चाहते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का criteria क्या है? बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, सबसे कम महिला साक्षरता दर है, सर्वाधिक निरक्षरता दर है, सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट है, सबसे कम gross enrolment ratio बिहार में है, अगर यह पैमाना माना जाए, तो सबसे अधिक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय बिहार को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। हर दसवां भारतीय बिहारी है, तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या बिहार की है, फिर भी आप बिहार को ही केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं देना चाहते हैं।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि बिहार को इसमें उपेक्षित क्यों रखा गया? महोदय, मैं सरकार से माँग करता हूँ कि बिहार में अधिक-से-अधिक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member Shri Sanjay Yadav: Shri A. A. Rahim (Kerala), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Shri Prem Chand Gupta (Bihar), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shri Ashok Singh (Madhya Pradesh), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Manoj Kumar Jha (Bihar), Dr. Faiyaz Ahmad (Bihar), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Jose K. Mani (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Niranjan Bishi (Odisha).

माननीय श्री मुजीबुल्ला खान। 'Demand to take Steps to Restore and Upgrade CPRI's Testing Infrastructure'.

Demand to take steps to restore and upgrade CPRI's testing infrastructure

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा): उपसभापति महोदय, आज मैं देश के एक महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूँ। माननीया वित्त मंत्री जी भी यहाँ मौजूद हैं, यह मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है कि उनको भी यह पता चले कि वे जो रुपया sanction करती हैं, उसका कैसा दुरुपयोग हो रहा है। Central Power Research Institute (CPRI) 1960 में बनी थी। हमारे देश में जो electrical equipment बनते हैं, वहाँ पर उनकी टेस्टिंग की जाती है और certificate दिया जाता है। उनका certification किया जाता है ताकि उनको उपयोग में लाया जाए, लेकिन पिछले 15 साल से उस

institute का जो synthetic testing laboratory mission है, जो functioning होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है और वह बंद पड़ा है। वह खराब हो गया है। जब हम लोग ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थाई समिति की तरफ से उस सेंटर पर गए थे, तो हम लोगों ने यह जानना चाहा कि वहाँ पर रिपेयर का काम क्यों नहीं हो रहा है? जब हम लोगों ने यह जानना चाहा कि वह रिपेयर क्यों नहीं हो रहा है, तो उन लोगों ने कहा कि उसको रिपेयर करने के लिए कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा है। इस पर मैंने कहा कि भाई, हमारा देश चांद पर पहुंच गया और तुमको मैकेनिक नहीं मिल रहा है! महोदय, उसका असली कारण यह है कि उस इंस्टिट्यूट का कोई अधिकारी वहां से नौकरी छोड़कर विदेश में जाकर दूसरी कंपनी में नौकरी कर रहा है, इसीलिए हमारे छोटे-छोटे एंटरप्रेन्योर्स को टेस्टिंग के लिए विदेश जाना पड़ता है। उनको अपनी इलेक्ट्रिकल ईक्विपमेंट्स को टेस्ट करवाने के लिए विदेश लेकर जाना पड़ता है। इसके लिए वे नीदरलैंड, साउथ कोरिया और इटली जाते हैं और जब वे वहां से सर्टिफिकेट ले आते हैं, तब जाकर उनकी बिक्री होती है।

सर, केंद्र सरकार ने उसको रिपेयर करने के लिए वर्ष 2021 में 40 करोड़ रुपये सैंक्शन किया था। वित्त मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि रिपेयर करने के लिए वर्ष 2021 में 40 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं, लेकिन आज तक रिपेयर नहीं हो पाया। इसका असली कारण यह है कि जो अधिकारी यहां की नौकरी छोड़कर बाहर की प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है, वह उनको वहां बुलाकर कमीशन देता है और लेता है, इसी के कारण आज तक इसको रिपेयर नहीं किया जा रहा है।

सर, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं डिमांड करना चाहता हूँ कि उसको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए और हमारे देश के जो पब्लिक इंटरप्राइजेज़ हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिक ईक्विपमेंट्स की छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ स्थापित की हैं, उन लोगों को मौका दिया जाए, ताकि वे देश में ही टेस्टिंग कराएं और खर्चे से बचें। क्या वे टेस्ट कराने के लिए विदेश जाएंगे, इटली जाएंगे, नीदरलैंड जाएंगे कोरिया जाएंगे? उपसभापति महोदय, यह क्या है? माननीय मंत्री जी यहां हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपने 2021 में जो 40 करोड़ रुपये दिए हैं, उसको उन लोगों ने अभी तक रिपेयर के लिए यूज़ नहीं किया है। वे उस पैसे का क्या कर रहे हैं, यह पता नहीं है। आप उसकी जानकारी लीजिए, इसके लिए मैं आपसे बहुत-बहुत अनुरोध करता हूँ, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Muzibulla Khan: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri A. A. Rahim (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Debashish Samantaray (Odisha) and Shri Sanjay Yadav (Bihar).

Now, Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade; 'Concern over increasing problem of unsolicited spam, fraudulent audio and video calls via WhatsApp and other social media platforms.'